



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2010/भाद्र 1, 1932

No. 237]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 2010/BHADRA 1, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

सं. 4 (आर.ई. : 2010)/2009-2014

फा. सं. 01/92/180/74/एएम 11/पीसी 6.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1), में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

1. परिशिष्ट 14-1-छ के पैरा 7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“7. ईओयू यूनितों की संयुक्त निगरानी :

(क) ईओयू के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा इकाई अनुमोदन समिति द्वारा छमाही आधार पर जैसे कि प्रत्येक वर्ष के अप्रैल-सितम्बर की अगली तिमाही में ईओयू द्वारा क्यूपीआर/ए पी आर भेजने के आधार पर की जाएगी। क्यूपीआर/एपीआर के प्रपत्र परिशिष्ट 14-1-च की विधिक वचनबद्धता में दिए गए हैं।

(ख) ईओयू की एनएफई की पुनरीक्षा इकाई अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी।

(ग) इस स्कीम का प्रचार करने के लिए, ऐसी बैठकों की तारीख से पहले स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाने चाहिए। स्थानीय उद्योग, एसोसिएशन या अन्य किसी संगठन, जिसकी इस क्षेत्र में अच्छी पहचान हो, के साथ मिलकर संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को भी शामिल किया जाए।

(घ) प्रत्येक मौजूद यूनिट की पुनरीक्षा उनकी कठिनाइयों को विस्तारपूर्वक जानने तथा उनका समाधान करने के लिए की जानी चाहिए। यूनिटों के कार्य निष्पादन में गिरावट/कमी के कारण जानने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा रुकावटों के निवारण के लिए यूनिटवार कार्रवाई योजना बनाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूनिटों की निर्यात संवर्धन रणनीति अगले कुछ वर्षों के लिए अंतिम लक्ष्य हों ताकि उनको यह जानकारी हो कि उन्हें क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं। चूककर्ता यूनिटों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि स्कीम के दुरुपयोग को हतोत्साहित किया जा सके।

(ङ) कार्यान्वयनाधीन यूनिटों हेतु, अलग-अलग पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(च) ऐसी जगहों में, यदि कोई बुनियादी सुविधाओं में कमी पाई जाती है तो जिला प्रशासन को सलाह दी जा सकती है कि वे ऐसी परियोजनाएं तैयार करें, जिन्हें कि राज्य सरकार के माध्यम से स्कीम फार सेन्ट्रल एसिस्टेन्स फार डेवलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अदर अलाइड एक्टिविटीज (ए एस आई डी ई) के अन्तर्गत मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाए।

(छ) संबंधित विकास आयुक्त संयुक्त पुनरीक्षा के आधार पर, वाणिज्य विभाग और सी.बी.ई.सी. की सूचना के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा ऐसे उपचारात्मक उपाय सुझाएगा जिससे कि चूककर्ता यूनिटें ई ओ यू स्कीम/सीमा-शुल्क अधिसूचना के अनुसार अपना दायित्व पूरा करें।”

2. परिशिष्ट 14-II को हटा दिया गया है।
3. आयात निर्यात प्रपत्र 8 में इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक-III को शामिल करते हुए संशोधन किया जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

पी. के. चौधरी, महानिदेशक,
विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

अनुलग्नक-III

मान्य निर्यात लाभों के लिए गैर-दावा प्रमाण-पत्र

मैं, (नाम और पद नाम).....मैसर्स
.....(आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) की तरफ से
एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमने मैसर्स.....
(प्राप्तकर्ता का नाम और पता) को निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति
की है :—

क्रम सं.	बीजक सं. एवं तारीख	माल का विवरण	इकाई	मात्रा	मूल्य
1.					
2.					

हम विनिर्माता निर्यातक/आपूर्तिकर्ता हैं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में पंजीकृत हैं/पंजीकृत नहीं हैं और उपर्युक्त आपूर्ति माल के संबंध में सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। हमने उक्त माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर छूट भी प्राप्त नहीं की है।

या

हम आपूर्तिकर्ता हैं और हमारा/हमारे सहायक विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में पंजीकृत है/हैं/पंजीकृत नहीं है/हैं और उक्त आपूर्ति माल के लिए सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमने उपर्युक्त आपूर्ति माल के संबंध में कोई अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है और उनका कोई लाभ नहीं उठाया है (शुल्क वापसी दावों के संबंध में लागू)।

हम यह भी कहते हैं कि हमने मान्य निर्यात के लिए कोई लाभ नहीं लिया है और न ही लेंगे और यदि मैसर्स
(प्राप्तकर्ता का नाम और पता) उपर्युक्त आपूर्तियों पर मान्य निर्यात लाभ प्राप्त करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(आपूर्तिकर्ता का नाम)

कार्यालय मोहर/स्टाम्प

(टिप्पणी.—गैर-दावा प्रमाण-पत्र फर्म के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए।)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd August, 2010

No. 4 (RE : 2010)/2009-2014

F. No. 01/92/180/74/AM 11/PC VI.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Volume 1).

1. Para 7 of Appendix 14-I-G shall be substituted as under :—

“7. Joint Monitoring of EOU units:

(a) The performance of EOUs would be reviewed by the Unit Approval Committee on six monthly basis i.e., April-September each year to be completed in the following quarter on the basis of QPRs/APR to be furnished by the EOUs. The formats of QPR/APR have been prescribed in the LUT at Appendix 14-I-F.

(b) Review of NFE of EOUs would be conducted by the Unit Approval Committee.

(c) For publicizing the scheme, advertisement in the local papers may be arranged before the date of such meetings. Promotion programmes may be organized in collaboration with local industry, Association or any other organization, which has good presence in the area. General Manager of District Industries Center may be associated.

(d) For each existing unit, review should be done at length to understand their problems and their possible resolution. Efforts should be made to identify the reasons for shortfall/poor performance and unit-wise action plan should be prepared for removal of bottlenecks. It should be ensured that the unit should have an export promotion strategy as well tentative targets for next few years, so that it has an idea as to what is to be achieved by them. Effective action should be taken against erring units to discourage any misuse of the scheme.

(e) For units under implementation, separate review be held so that their issues could be resolved.

(f) At such places, if any infrastructure gaps are noticed, District Administration may be advised to prepare projects, which can be routed through State Government to the Ministry for approval under Scheme for Central Assistance for Developing export infrastructure and other allied activities (ASIDE).

- (g) Based on the Joint review Development Commissioner concerned would prepare a report for information of the Department of Commerce and CBEC and suggest corrective measures to enable the defaulting units to fulfill their obligation as per EOU Scheme/Customs Notification".

2. Appendix 14-II shall be deleted.
3. ANF 8 shall be amended by inserting therein Annexure-III appended to this Public Notice.

This issues in public interest.

P. K. CHAUDHERY, Director General of Foreign Trade and Additional Secy.

Annexure III

DISCLAIMER CERTIFICATE FOR DEEMED EXPORT BENEFITS

I, (Name and designation).....on behalf of M/s.(Name and address of the supplier) hereby certify that we have supplied the following goods to M/s.....(Name and address of the recipient):

S.No.	Inv.No.& date	Description	Unit	Qty.	Value
		of goods			
1.					
2.					

We are the manufacturer exporters/suppliers and are registered/not registered with Central Excise and have not availed CENVAT facility in respect of the aforesaid supplied goods. We have also not availed of rebate on the raw material used for manufacture of said goods.

or

We are the suppliers and our supporting manufacturer(s) is/are registered/not registered with Central Excise and have not availed CENVAT facility in respect of the aforesaid supplied goods.

We also certify that we have not been issued any Advance Authorization/Duty Free Import Authorization in respect of the aforesaid supplied goods and have not availed any benefit therein (applicable in respect of draw back claims).

We further state that we have not drawn nor will draw any benefit for deemed export and we have no objection if M/s.....(Name and address of the recipient) draws the deemed export benefit on the Supplies mentioned above.

Yours faithfully,

(Authorized Signatory)

(Name of the supplier)

Official Seal/Stamp

(Note.—Disclaimer certificate is to be given on letter head of the firm).